E-newsletter
August-2016

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

LSG
Local Self Government
Rajasthan

Minimum Government, Maximum Governance

सत्यमेव जयते

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Local Self Government Rajasthan

The Department of local self Government, Rajasthan is the controlling Department of all municipalities for all administrative purposes. It also performs monitoring and co-ordination function at the state level for all the 188 municipal bodies of the state.

Functions of Department of Local Self Government Rajasthan

* ***Appointment of OICs/Advocate in Court Cases, vetting of reply, opinion on judgment, decision for appeal or no appeal, scrutiny of Bye-Laws and Rules and Amendments in Acts and Rules.***
* ***Approval of Budget of ULBs and released of funds regarding Special Grant, General Grant, SFC, TFC, Grant (in Lieu of Octroi) and State/Centrally Sponsored Schemes/Programme.***
* ***Disposal of matters related to transfer, establishment, DPCs related to officers and staff of ULBs, DDR offices and Directorate.***
* ***Extension and Exclusion of Municipal boundary, Election of Municipal Boards.***
* ***Implementation of HRD Plan for elected representatives, and officials of ULBs.***
* ***Implementation of Poverty Alleviation and social responsibilities Programmes.***
* ***Issuance of Financial, Administrative and Technical Sanctions which are not in the Jurisdiction of the elected board.***
* ***Preparation of Annual Plan/District Plan/Action Plan/DPRs related to various GoI/GoR schemes/Programmes.***

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Various Schemes

AMRUT – (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)

Urban Infrastructure Development of 29 Towns > 1.0 lac population.

Total Estimated Project cost Rs 4500 cr (50% GoI, 30% GoR, 20% ULB)

Components to be covered - Water supply, Sewerage network, Septage management, Storm water drainage, Urban Transport, Green spaces and parks.

HRIDAY-Heritage Cities Infrastructure Development & Augmentation

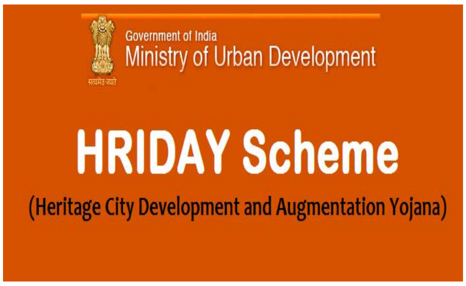

- Ajmer – Pushkar nominated under HRIDAY– 100% grant by GoI.
- City HRIDAY Plan for Rs 48.00 cr. approved by MoUD, GoI.

National Urban Livelihood Mission (NULM)

- Focus on Skill Training & Placement and Capacity Building / Self Employment.
- Major components- Shelter for Urban Homeless, Support to Urban Street Vendors.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

स्मार्टराज कॉल सेन्टर

आम जनता की शिकायतों को हल करने का अनूठा प्रयास ....

स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में आमजन के लिए स्मार्ट राज कॉल सेन्टर दिनांक 11.05.2015 माननीय मंत्री महोदय श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन कर प्रारंभ किया गया है। जिसके टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 है जिसमें आईवीआर नं0 2 तत्पश्चात् 1 पर आमजन की कॉल प्राप्त कर उन्हें विभाग के संबंध में चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ नगरीय निकायों व विभाग से संबंधित शिकायतें सम्पर्क पोर्टल पर निरंतर दर्ज की जा रही है। 11 मई से 18 नवम्बर, 2015 तक 50506 कॉल प्राप्त हुई एवं 5844 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 2840 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

दर्ज शिकायतों को संबंधित निकायों / निदेशालय के अनुभागों को प्रेषित किया जाता है तथा जो शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित है, उन्हें संबंधित विभागों में स्थानांतरित किया जाता है। शिकायतों के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉल सेन्टर के नोडल अधिकारियों को कॉल कर अवगत / निर्देशित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त जवाब को भी निरंतर दर्ज कर दैनिक रिपोर्ट बनाई जाती है।

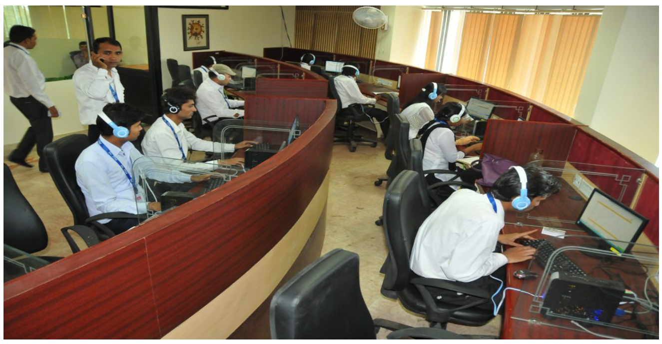

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

स्वच्छ भारत मिशन

खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान ....

स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है जो 02 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक भारत को 'खुला शोच मुक्त भारत' घोषित करना है। स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा LSGD, GoR को नोडल विभाग बनाया गया।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत (शहरी) के 10 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा 'स्वच्छ राजस्थान सप्ताह' मनाया गया जो कि 02 अक्टूबर, 2014 को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा स्वच्छता शपथ लिये जाने के साथ सम्पन्न हुआ।

इसी सप्ताह को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए "स्वच्छ राजस्थान अभियान" चलाया गया जो दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन अभियानों के दौरान साफ, सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया और सामुदायिक जागरूकता हेतु प्रभात फेरी, रेली, श्रमदान आदि जैसे कार्य संपादित हुए। तत्पश्चात राज्य की समस्त निकायों द्वारा 08 नवम्बर से 14 नवम्बर तक सफाई अभियान चलाया गया जो बालदिवस पर सम्पन्न हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हेतु 12 फरवरी 2015 को राज्य स्तर, जिला स्तर व शहरी स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य के 187 शहरी निकायों में 9 मार्च से 27 मार्च तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत शहरों में नालों की सफाई, रोड़ की सफाई, पार्को की सफाई, रोड़ लाइटों का रखरखाव, स्कूलों व राजकीय कार्यालयों की सफाई, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान (सर्वे द्वारा) आदि शामिल थे साथ ही शहरी स्तर पर प्रत्येक निकायों द्वारा सामुदायिक जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिनमें वार्ड सभाऐं, नुक्कड नाटक, अपील, रेली आदि आयोजित की गई जिससे जन समुदाय को स्वच्छत्ता व सफाई आदि के महत्व का पता चल सके व खुले में शौच का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों का भी ज्ञान दिया गया। अगस्त 2015 को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में सहयोग व सभी नगरीय निकाय से संपर्क स्थापित कर स्वच्छ भारत मिशन कार्य को गति देने हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) का गठन किया गया है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक संभाग की स्वच्छ भारत मिशन पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन सी.एम.ए. आर. द्वारा कराया गया प्रथम चरण (9 April, 16 April, 28 April & 29 April, 2015) द्वितीय चरण में परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) तथा सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान व CSC के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा (26th October to 04th November, 2015) तकनीकी अधिकारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के प्रत्येक घटक को विस्तार पूर्वक बताया गया और प्रत्येक शहरी निकाय को लक्ष्य बताये गए तथा 2015–16 के और संपूर्ण मिशन अवधि 2019 के बारे में जानकारी दी।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

अमृत मिशन योजना

शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अटल प्रयास...

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 28 शहरों के ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाने के लिए दो दिवसीय ''हैण्ड होल्डिंग'' कार्यशाला (10 व 11 अगस्त) का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में किया गया।

इस कार्यशाला में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि अमृत योजना के तहत बनाये जाने वाले ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' सम्बन्धित शहर के नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाया जाये। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में पूर्व में रही कमियों को अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में नहीं दोहराया जाये। उन्होनें कहा कि शहरों में सीवरेज योजनाओं के प्रारम्भ करने से पूर्व में जारी पेयजल योजनाओं के सशक्तीकरण एवं सेवा स्तर को सुधारते हुए कवरेज (आवृत) क्षेत्र में गेप पूरा किया जाए। उन्होने बताया कि अमृत योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल कवरेज (पेयजल एवं सीवरेज) को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इन क्षेत्रों के गेप को पूरा होने पश्चात् ही अन्य क्षेत्रों में शहरी परिवहन एवं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज को प्रारम्भ किया जाये।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अमृत योजना में शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत योजना में सम्मिलित प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वर्ष में एक उद्यान का विकास किया जाना आवश्यक है। उन्होनें बताया कि अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के तहत एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट कंसलटेन्ट की नियुक्ति की जायेगी जिसका कार्य शहरों का ''सिटी लेवल सर्विस इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाकर तद्नुसार राज्य की वार्षिक योजना तैयार कर अनुमोदन पश्चात् डीपीआर तैयार करना एवं प्राजेक्ट के क्रियान्वयन का सुपरविजन करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री दिनेश कुमार के साथ विशेषज्ञों के दल ने ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' (पेयजल सीवरेज शहरी परिवहन स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एवं उद्यानों) के बनाये जाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी, मुख्य अभियंता रूफडिको श्री एस.के. गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रूफडिको श्री ललित करोल तथा 28 शहरी निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं अभियन्ता उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन RUIFDCO तथा CMAR के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एनर्जी सेविंग परियोजना एवं अमृत योजना की समीक्षा

स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक श्री पुरूषोत्तम बियाणी की अध्यक्षता में मंगलवार को निदेशालय स्थानीय निकाय में राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एल.ई.डी. लाईट प्रोजेक्ट एवं अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) योजना की समीक्षा की गई।

बैठक में निदेशक श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अपनी–अपनी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सख्त कार्यवाही करें तथा सम्पत्ति विरूपण करने वालों के खिलाफ स्थानीय थानों में मामले दर्ज करवायें।

निदेशक श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए बताया कि सेल्फ एमप्लॉयमेंट रोजगार योजना के तहत बैंक द्वारा अब तक 2545 व्यक्तियों को 11 करोड़ 60 लाख का लोन दिया जा चुका है। बेघर व्यक्तियों के लिए 15 आश्रय स्थल बनाये जा चुके है तथा 72 आश्रय स्थलों को चलाने के स्वीकृती जारी की जा चुकी है। स्ट्रीट वेण्डर के सर्वे 14 नगरीय निकाय में पूर्ण हो चुके है तथा 18 नगरीय निकायों में जारी है। अब तक 40 नगरीय निकायों में 4000 स्वयं सहायता समूह बनाये जाने थे। जिनमें से अब तक 4100 स्वयं सहायता समूह बनाये जा चुके है तथा 7263 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से दिया गया है।

बैठक में अमृत योजना के अन्तर्गत स्मार्ट राज योजना की समीक्षा करते हुए नगरीय निकायों के अधिकारियों ने बताया कि सभी नगरीय निकायों में प्रापर्टी सर्वे का कार्य तेजी से जारी है। लगभग सभी नगरीय निकायों में वेबसाईट बनाने का कार्य भी पूरा हो चुका है। इसी प्रकार स्मार्ट राज मॉड्यूल बनाने का कार्य जारी है। निदेशक श्री पुरूषोत्तम बियाणी ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये कि वे प्रोपर्टी सर्वे के फॉर्मो की जॉच करें एवं किये जा रहे सर्वे की दैनिक समीक्षा करें तथा वेबसाईट पर राजकीय आदेशों एवं नियमों को अपलोड करें।

एल.ई.डी. लाईट प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान बैठक में नगरीय निकायों के अधिकारियों के बताया कि उनके यहाॅ पर फेज वायर अर्थिंग, स्विच बोर्ड, टाईमर, केबलिंग का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा

एल.ई.डी. लाईट प्रोजेक्ट में आने वाली समस्याओं का निदान नगरीय निकाय स्तर पर किया जा रहा है। श्री बियाणी ने निर्देश दिये कि नगरीय निकायों में एनर्जी सेविंग परियेाजना के दौरान लगाई जा रही एल.ई.डी. लाईटों कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाये।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए श्री बियाणी ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये कि माह दिसम्बर तक सभी नगरीय निकायों को अपने–अपने क्षेत्रों को खुले में शौच को रोकने का कार्य करते हुए अपने–अपने शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। उन्होनें घर–घर शौचालय बनाने की योजना में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में पाली, बारां, झालावाड़, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर नगरीय निकायों के अधिकारियों ने बताया कि उनके यहॉ डोर–टू–डोर कचरा एकत्रित करने की योजना प्रारम्भ कर दी गई है।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये मॉडल बिल्डिंग बॉयलॉज–2016, पेट्रोल पम्प स्थापना के नियम लागू

राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में 75 प्रकरणों को स्वीकृती प्रदान की गई

राज्य के विभिन्न नगर पालिकाओं एवं परिषदों से संबंधित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की षष्ठम बैठक सोमवार को स्वायत्त शासन भवन के कांफ्रेस हॉल में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में नगरीय निकाय क्षेत्रों के 77 भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में से 75 प्रकरणों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 2 प्रकरणों को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्णय लिया गया।

बैठक में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प के लिए भारत सरकार की शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये मॉडल बिल्डिंग बॉयलॉज–2016 के तहत निर्धारित पेट्रोल पम्प स्थापना के नियमों को लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में रिसर्जेण्ट राजस्थान के दौरान किये गये 4 एम.ओ.यू. सम्बन्धित प्रकरण रामगढ़ शेखावाटी में वाटर फिल्टर प्लांट को तथा पदमपुरा, चाकसू, झून्झूनूं में रिसोर्ट्स योजना को स्वीकृती प्रदान की गई।

भू–उपयोग परिवर्तन के जिन 75 प्रकरणों पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया इन प्रकरणों में मुख्य रूप से ब्यावर, सरवाड़, किश्नगढ़, नावां, आसीन्द, नागौर, मकराना, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह, भीलवाड़ा, विजयनगर, जहाजपुर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, केसरीसिंहपुर, नोहर, पदमपुर, चुरू, रतनगढ़, राजगगढ़ (चुरू), रामगढ़ शेखावाटी, दौसा, फुलेरा, चाकसू, चिड़ावा, झून्झूनू, रिंगस, पोकरण, भीनमाल, जैतारण, सोजत सिटी, आमेट, उदयपुर, छोटी सादढ़ी, बड़ी सादड़ी, डूंगरपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, राजसमंद, सलूम्बर, चिड़ावा, बयाना, तिजारा, निवाई के प्रकरण शामिल है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि स्मार्ट राज परियोजना के तहत राज्य की समस्त नगरीय निकायों में ई–गर्वनेंस परियोजना क्रियान्विति की जा रही है। परियोजना के तहत आम नागरिकों को नगरीय निकायों से संबंधित समस्त कार्य यथा नगरीय विकास कर, भू–रूपान्तरण, भू उपयोग परिवर्तन, भवन मानचित्र अनुमोदन, अग्मिशमन आपत्ति अन्य किसी भी प्रकार की एनओसी आदि का कार्य ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत प्रारम्भ कर

दिया गया है। उन्होनें बताया कि प्रक्रिया के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ 90 ए के तहत रूपान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन एवं भवन मानचित्र अनुमोदन को राज्य सरकार की सिंगल विंडो क्लियरेंस सिंस्टम समायोजित कर आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी

गई है। इनमें से 90 ए एवं भू–उपयोग परिर्वतन का आवेदन सिंगल विंडो की वेबसाईट पर एवं भवन–मानचित्र अनुमोदन का ऑनलाईन आवेदन सिंगल साईन ऑन वेबसाईट पर प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदन भी प्राप्त होने शुरू हो गये है। इस प्रक्रिया से जहॉ एक ओर कार्य में तेजी आयेगी वही दूसरी ओर कार्यो में पारदर्शिता आयेगी। प्रक्रिया के तहत आवेदक ऑन–लाईन भुगतान भी कर सकेगा तथा अपने कार्य की प्रगति सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी प्राप्त कर सकेगा। उन्होने सभी नगरीय निकायों से आये हुये जिला नगर नियोजकों को निर्देश दिये कि सभी नगरीय निकाय बिल्डिंग प्लान स्वीकृती ऑन–लाईन बिल्डिंग प्लान प्रक्रिया के तहत ही देना सुनिश्चित करें।

अमृत योजना के तहत जारी 1275 करोड़ के 11 शहरों के सीवरेज कार्य के Letter of Acceptence (LoA) को किया निरस्त

रूडसिको द्वारा अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लि. व टाटा प्रोजेक्ट्स के संयुक्त बिडर को जारी 1275 करोड़ के 11 शहरों के सीवरेज कार्य के Letter of Acceptence (LoA) को निरस्त कर दिया है।

रूडसिको द्वारा यह कार्यवाही एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लि. व टाटा प्रोजेक्ट्स के संयुक्त बिडर के द्वारा हाल ही में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में की गई अवांछनीय गतिविधि को देखते हुए की गई है। उपरोक्त परियोजना की शीघ्र ही नये सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत डूंगरपुर शहर ‘‘खुले मे शौच मुक्त’’ घोषित

नगर परिषद डूंगरपुर ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत डूंगरपुर शहर को खुले मे शौच मुक्त घोषित किया है।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय रहित भवनों में शौचालय निर्माण का कार्य सम्पूर्ण शहर में करवा दिया गया है। उन्होनें बताया कि डूंगरपुर शहर में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जा रहा है। इसका भौतिक सत्यापन जिला कलेक्टर डूंगरपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा करवाया गया है। इस संबंध में नगर परिषद डूंगरपुर के सभापति एवं शहर के सभी 30 वार्डो के वार्ड पार्षदगणों ने भी भौतिक सत्यापन किया है। उन्होनें बताया कि नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा डूंगरपुर शहर को 30 जुलाई, 2016 से खुले में शौच मुक्त शहर घोषित किया गया है।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने डूंगरपुर शहर को खुले में शौच मुक्त शहर घोषित करने पर जिला कलेक्टर डूंगरपुर तथा नगरपरिषद डूंगरपुर के सभापति एवं पार्षदगणों को बधाई दी है।

प्रदेश के 29 अमृत शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी

एनआईसी सेन्टर में एक दिवसीय विडियों कांफ्रेसिंग सह कार्यशाला का आयोजन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 29 अमृत शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी कार्यकारी एवं जनसहभागिता को बढ़ावा दिये जाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 06 अगस्त, 2016 शनिवार को एक दिवसीय विडियों कांफ्रेसिंग सह कार्यशाला का आयोजन जिला कलेक्टर, एनआईसी सेन्टर में प्रातः 10:00 बजे से सांय काल 05:00 बजे तक किया जायेगा।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यो की क्रियान्विति का सर्वेक्षण शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करवाया जाकर देश के 73 शहरों की रेंकिंग की गई थी। इस की निरन्तरता में वर्तमान में देश के 500 शहरों की रेंकिंग जनवरी 2017 में की जानी है। जिसमें प्रदेश के 29 अमृत शहरों को सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया है। पूर्व में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 31 मई, 2016 को 29 अमृत शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार से जारी सर्वेक्षण निर्देशिका प्रेषित की जा चुकी है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों को रहने का बेहतर स्थान बनाने की ओर मिलकर बहुसंख्या में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा समाज के सभी वर्गो में जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण के शहरों को स्वच्छ बनाने में और नागरिकों को सवाएं प्रदान करने में सुधार करने एवं शहरों और कस्बों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है।

उन्होनें इस सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण घटक नागरिकों की भागीदारी है, सामाजिक मीडिया और अन्य परम्परागत मीडिया चैनलों का भी राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयोग किया जायेगा। जिसमें जनता को सर्वेक्षण और सर्वेक्षण विधि के उद्देश्यों के बारे में जनता को जानकारी दिये जाने के साथ–साथ सर्वेक्षण में उनकी भागीदारी के महत्व को प्रबलित करना है ताकि सभी नागरिकों को उच्च स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

विडियो कांफ्रेसिंग सह कार्यशाला का शुभारम्भ प्रातः 10:00 बजे होगा जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी जायेगी तथा शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण दिशा–निर्देश व निर्देशिका का वितरण किया जायेगा। विडियो विडियो कांफ्रेसिंग के दौरान प्रातः 11:00 बजे से केन्द्रिय शहर विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू द्वारा सम्बोधित किया

जायेगा। इस दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एनआईसी सेन्टरों पर उपलब्ध प्रतिभागियों को स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी दी जायेगी।

एक दिवसीय विडियो कांफ्रेसिंग सह कार्यशाला का आयोजन

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छता मिशन को जन आन्दोलन बनाये जाने की अपील की

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छता मिशन को जन आन्दोलन बनाये जाने की अपील की है। उन्होनें 500 अमृत शहरों के महापौरों, पार्षदों, जिला कलेक्टरों, आयुक्तों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि वे अधिक से अधिक समय निकाल कर स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये तथा आम जनता से समन्वय स्थापित कर अपने–अपने शहर को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये।

यह अपील केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 500 अमृत शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी कार्यकारी एवं जनसहभागिता को बढ़ावा दिये जाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 06 अगस्त, 2016 को आयोजित एक दिवसीय विडियो कांफ्रेसिंग सह कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए की।

विडियों कांफ्रेंसिंग सह कार्यशाला में स्टेट मिशन निदेशक, जिला कलेक्टर, प्रदेश के 29 अमृत शहरों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष, पाषर्दगण, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभियन्तागण भाग लिया। इस अवसर पर राज्य सचिवालय में स्थित एनआईसी सेन्टर में निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी, मुख्य अभियन्ता श्री के.के. शर्मा तथा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर उन्होनें बताया कि 04 जनवरी, 2017 को देश के 500 अमृत शहरों के मध्य स्वच्छता के लिए Quality Council of India (QCI) सर्वेक्षण किया जायेगा। पूर्व में शहरी विकास मंत्रालय भारत

सरकार द्वारा देश के 73 शहरों की स्वच्छता के लिए रैंकिंग की गई थी। उन्होनें बताया कि सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों को रहने का बेहतर स्थान बनाने की ओर मिलकर बहुसंख्या में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा समाज के सभी वर्गो में जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण के शहरों को स्वच्छ बनाने में और नागरिकों को सवाएं प्रदान करने में सुधार करने एवं शहरों और कस्बों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है। उन्होने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान रैंकिंग निर्धारण जिन बिन्दुओं पर किया जायेगा उनमें कचरा एकत्रिकरण के लिए 40 अंक, प्रोसेसिंग के लिए 20 अंक, शहर में जनसुविधाओं के लिए 30 अंक तथा खुले में शौच मुक्त शहर के लिए 05 अंक एवं जनजागृति के लिए IEC Activity के लिए 05 अंक कुल 100 अंक निर्धारित किये गये है।

श्री नायडू ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से देश का हर नागरिक दिल से जुड़ा है। मौहल्ला विकास समितियों ने अपने–अपने स्तर पर अपने–अपने मौहल्लो को साफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्होनें कहा कि स्वच्छता मिशन को राजनितिक रूप नहीं देकर एक जन आन्दोलन बनाये। उन्होनें बताया कि स्वच्छता मिशन को जन–जन में पहुॅचाने के लिए देश के मिडिया ने निःस्वार्थ कार्य किया है। कई समाचार पत्रों में स्वच्छता मिशन को जनआन्दोलन बनाने के लिए अलग से स्थान दिया जाता है। ऐसा ही देश के प्रमुख टी.वी. चैनल्स ने भी किया है। उन्होनें कहा कि विभिन्न कम्पनीयों संस्थाओं को अपने शहर को साफ रखने में सहयोग करना चाहिए। उन्होनें सभी शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाने घर–घर में शौचालय निर्माण पर जोर दिया। उन्होनें कहा कि देश की असली तरक्की राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त बनाना है। उन्होनें सभी नगरपालिकाओं से अपेक्षा की कि वहॉ पर कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से हो तथा घर–घर कचरा संग्रहरण का कार्य किया जाये एवं युजर चार्जेज लिया जाये। हर परिवार में स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता हो एवं घरेलू टॉयलेट का उपयोग किया जाये।

कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास मंत्री शहरी वेंकैया नायडू ने तीन पुस्तकों जिनमें, स्वच्छता सर्वेक्षण गाईड बुक (पुस्तक में सभी सर्वेक्षण किये जाने वाले शहरों के लिए 112 प्रश्न होंगे, जिसके आधार पर रैंकिंग होगी), आईडिया बुक व म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैन्यूअल का लोकार्पण किया। इस दौरान पुनः नगर निगम को देश में सॉलिड वेस्ट मैनजमेंट के लिए तथा गुवाहाटी, कोच्ची व आन्ध्रप्रदेश के तीन स्वच्छता कर्मियों को एवं गैर सरकारी संस्थानों (एनजीओ), विकास समितियों को भी स्वच्छता मिशन में श्रेष्ठ कार्य करने पर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान धनबाद शहर एवं मैसूर सिटी द्वारा भी स्वच्छता मिशन के दौरान किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि मैसूर शहर गत सर्वेक्षण में देश में प्रथम स्थान पर रहा था।

कार्यक्रम मे शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री राजीव गोवा ने बताया कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी माह में होगा इस सर्वेक्षण में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सभी शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी, जिससे देश के सभी शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ बन सकेंगे। उन्होनें बताया कि कार्यशाला के माध्यम से सभी शहरों को सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक श्री प्रवीण प्रकाश ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में आमजनता के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टरों की प्रमुख भूमिका है।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे करेंगी अजमेर में 100 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 14 अगस्त, 2016 को अजमेर में, स्वायत्त शासन विभाग के 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस 14 अगस्त, 2016 को अजमेर में राशि रूपये 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, का शुभारंभ किया गया।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एवं रेल्वे के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर में बनाये जाने वाले दो आरओबी प्रथम डीएवी कॉलेज के पास राशि रूपये 38 करोड़ तथा द्वितीय डेयरी के पास राशि रूपये 35.75 करोड़ का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे करेंगी। उक्त दोनो आरओबी के निर्माण पर होने वाले व्यय का भार 50—50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं रेल्वे विभाग द्वारा उठाया जायेगा।

उन्होनें बताया कि हृदय योजना के तहत राशि रूपये 35 करोड़ की पॉच परियोजनाओं का शिलान्यास किया जायेगा। जिसमें नया बाजार, हैरिटेज वॉक राशि रूपये 5.47 करोड़, आनासागर, फायसागर, लेक फ्रंट डवलपमेंट राशि रूपये 16 करोड़, सुभाष उद्यान कल्चरल पार्क राशि रूपये 8.3 करोड़, जयपुर रोड़ का हैरिटेड कंजरवेशन राशि रूपये 3.50 करोड़, पुष्कर हैरिटेज वॉक राशि रूपये 6.16 करोड़ शामिल है। उन्होने बताया कि हृदय योजना के तहत उपरोक्त कार्यो में हैरिटेज कंजरवेशन फसाड इम्प्रुवमेंट, फुटपाथों का निर्माण एवं सुधार, पब्लिक टॉयलेट का निर्माण एवं सुधार, अण्डर ग्रारण्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, पार्किंग स्पेस निर्माण, लैण्ड स्केपिंग, नालों को कवर करने का कार्य किया जायेगा।

डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे पब्लिक बायसिकल शेयरिंग का शुभारंभ भी किया। इस योजना के तहत अब तक 10 साईकिल स्टेशनों में से 4 स्टेशनों का कार्य पूर्ण हो चुका है। यहॉ पर प्रत्येक साईकिल स्टेशन पर 20 साईकिलें उपलब्ध होंगी। उक्त परियोजना पीपीपी मोड पर आधारित है। जिसमें साईकिल स्टेशन का निर्माण नगर निगम अजमेर द्वारा करवाया गया है तथा साईकिल संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाई जायेंगी। उक्त परियोजना पर लगभग राशि रूपये 1 करोड़ व्यय होगा।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि अजमेर में, एनर्जी सेविंग परियोजना (एलईडी लाईट) का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे इस अवसर पर ''सेन्ट्रलाईज कम्प्यूटर सिस्टम'' का लोकार्पण किया।

उन्होनें बताया कि अक्षय फाउण्डेशन व नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से अजमेर में अक्षय कलेवा योजना प्रारम्भ की जा रही है। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। योजना के तहत गरीब लोगों को राशि रूपये 10 में हाईजिनिक भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।

डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि अजमेर में बनाये गये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे द्वारा किया गया।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) कोष से नगरीय निकायों को आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) कोष से प्रदेश की एक लाख तक की आबादी वाले नगरीय निकायों को आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों यथा सड़क, नालियॉ, जल निकास, वाटर बॉडिज, बाढ़ नियंत्रण कार्य, शमशान घाट (सभी धर्मो के) इत्यादि के संरक्षण एवं विकास के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश में नगरीय विकास की गति को बढ़ाने के लिए राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) कोष में संशोधन किया गया है तथा इसमें नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। इस कोष से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों को आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों यथा सड़क, नालियॉ, जल निकास, वाटर बॉडिज, बाढ़ नियंत्रण कार्य, शमशान घाट (सभी धर्मो के) इत्यादि के संरक्षण एवं विकास के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

उन्होंने बताया कि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) कोष से उपलब्ध राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़को की निर्धारित सड़क सीमा में सुरक्षात्मक वाहन परिचालन के लिए आवश्यकतानुसार चार दिवारी, तारबन्दी एवं वैकल्पिक कार्य किये जा सकेंगे साथ ही नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की पूर्ति के लिए 2.50 करोड़ रूपये प्रति नगरीय निकाय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।

उन्होनें कहा कि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) कोष से जयपुर मेट्रो रेल निगम को गत वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों का 25 प्रतिशत अथवा गत वर्ष की संचालन हानि अथवा राशि रूपये 50 करोड़ जो भी कम हो तक की सहायता भी उपलब्ध करवायी जा सकेगी।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Contact Us

Local Self Government

Shri Rajpal Singh Shekhawat(Honorable Minister UDH)
(O)Ph No.+91141-2227533,

Shri Manjeet Singh(IAS) - Principal Secretary
Ph No. +91141-2227128

Shri Purushottam Biyani (IAS) Director and Joint Principal Secretary
Ph No.+91141-2222403
Fax: 0141-2222403

Call Center Toll free No.:- 1800-180-8127

Office-Local Self Government Department (Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur) G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur - Rajasthan -India